प्रेषक.

दिलीप जावलकर, सचिव, उत्तराखण्ड शासन्।

सेवामें,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून :: दिनांक :: 05 जून, 2023

विषयः बैंक खाते के माध्यम से संचालित हो रही राज्य पोषित योजनाओं को केन्द्र सरकार के एस. एन.ए. मॉड्यूल की भांति संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के अध्याय—16(ए) में राजकीय सहायक अनुदान (Grant in Aid) से सम्बन्धित सामान्य नियमों का विस्तार से उल्लेख है, परन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि राजकीय अनुदान सम्बन्धि ात मानक मद '55-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान', '56-सहायक अनुदान (गैर वेतन)' तथा अन्य राज्य पोषित विभागीय योजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि शासन की अनुमति के बिना बैंक खाते में पार्क की जा रही है, जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण रखने व कुशल वित्तीय प्रबन्धन हेतु समस्त राज्य पोषित विभागीय योजनाओं, जिनका संचालन बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है, को निम्नांकित प्रक्रियानुसार संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--
 - प्रारम्भिक चरण में यह व्यवस्था अब तक पूर्व से बैंक से संचालित राज्य पोषित योजनाओं पर ही लागू होगी।
 - सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त बैंक खाते के अतिरिक्त संचालित समस्त बैंक खातों (ii) को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।
 - यदि किसी प्रयोजन विशेष हेतु बैंक खाते की आवश्यकता हो या प्रचलित बैंक खाते में परिवर्तन हो तो कारण बताते हुए वित्त (व्यय नियंत्रण) विभाग की अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाएगी।
 - विभागाध्यक्ष / धनराशि व्ययकर्ता स्तर पर सहायक अनुदान एवं बैंक खातों के माध्यम से संचालित अन्य योजनाओं के संचालन हेतु एक बैंक खाता चिन्हित किया जायेगा, जिसमें आई.एफ.एम.एस. के माध्यम से योजना की धनराशि अन्तरित की जायेगी तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के 01 अप्रेल की ओपनिंग बैलैंस प्रविष्टि अनिवार्य अंकित की जायेगी। परन्तु वित्तीय वर्ष 2023—24 के संदर्भ में दिनांक 01 जुलाई, 2023 को ओपनिंग बैलैंस प्रविष्टि को अंकित किया जाएगा।
 - वित्तीय वर्ष के अन्त में खाते में जमा ब्याज की धनराशि राजकोष के सुसंगत प्राप्ति शीर्षक में अनिवार्य रूप से जमा की जायेगी।

1/127546/2023

- (vi) वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड—5 भाग—1 अध्याय—16(ए) में उल्लिखित प्रकिया का पूर्णतः पालन किया जाये।
- (vii) राज्यपोषित योजनाओं से सम्बन्धित धनराशि एकल नोडल खाते (SNA) से इत्तर किसी भी अन्य खाते में अन्तरित नहीं किया जायेगा।
- (viii) यह व्यवस्था संलग्न मानक परिचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के अनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2023 से लागू होगी तथा तब तक विभागों द्वारा तत्संबंधी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएंगी।
- 3- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय, Signed by Dilip Jawalkar Date: 05-06-2023 11:16:11 (दिलीप जावलकर) सचिव।

संख्या : 1275 पर्भ) / XXVII (1) / 2023 तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 2— निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
- 5— महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड।
- 6- क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून।
- 7- आयुक्त, कुमाऊं / गढवाल मण्डल, नैनीताल / पौड़ी।
- 8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 10— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि आई.एफ.एम.एस. सॉफ्टवेयर में उक्त सम्बन्धित आवश्यक संशोधन सुनिश्चित कर लें।
- 11- सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, देहरादून।
- 12- गार्ड फाइल।

(दिलीप जावलकर) सचिव।